(ख) उन सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरु किया जाएगा और इन नई परियोजनाओं को कब तक लागू कर दिये जाने का निश्चय है तथा इन्दिरा गांधी नहर को कब तक पूरा कर लिया जाएगा और इस पर और कितना खर्च किया जाएगा ;

(ग) इस समय देश में कुल कितने हैक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है और आठवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा ; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई परियोजना पर कितनी राशि खर्च किए जाने की सम्भावना है और राजस्थान में परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जकब) : (क) लगभग 3.7 मिलियन हैक्टेयर । आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) सिंचाई सैक्टर के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रुप नहीं दिया गया है । इंदिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-एक को सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है, जबकि परियोजना के चरण-दो, जिसमें नहर प्रणाली की परिकल्पना की गयी है, को सन् 2002 तक पूरा करने का कार्यक्रम है । मार्च, 1990 से आगे लाई जाने वाली परियोजना की शेष राशि लगभग 1260 करोड़ रुपए आंकी गयी है ।

(ग) लगभग 69.8 मिलियन हैक्टेयर । आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

राजस्थान से लगी और पाकिस्तान सीमा पर तस्करी

312. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान (मार्च 1989 तक) राजस्थान से लगी भारत-पाक सीमा पर कितने हथियार, तस्करी का माल, नशीली औषधियां तथा अन्य वस्तुएं पकड़ी गई हैं और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है और पकड़े गये माल का मूल्य क्या है ;

(ग) सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सीमा के रास्ते तस्करी के क्रियाकलापों में वृद्धि हुई है ; और

(घ) इस सीमा पर तस्करी को रोकने और संदिग्ध लोगों को पकड़ने पर सरकार प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च कर रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) : भारत पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा वर्ष 1986, 1987, 1988 और 1989 (मार्च तक) के दौरान पकड़े गए तस्करी के सामान की मात्रा और कीमत तथा गिरफ्तार किए गए तस्करों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण [देखिए परिशिष्ट 151, अनुपत्र सं. 13] जब्त किया सभी सामान तथा पकड़े गए व्यक्तियों को क्रमश: सीमा शुल्क प्राधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया गया । पकड़े गए तस्करों के खिलाफ कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करना सीमा शुल्क/राज्य पुलिस का कार्य है।

सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को और सुदृढ़ कर दिया गया है तथा वे घुसपैठ,

सामान की तस्करी इत्यादि को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

(घ) घुसपैठ, तस्करी, पशुओं की चोरी तथा सीमा पर होने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए भारत-पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की बड़ी संख्या में बटालियनें तैनात की गई हैं। सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन बनाने पर इस समय आवर्ती व्यय लगभग 2.5 करोड़ रुपए है तथा गैर-आवर्ती व्यय 2.5 करोड़ रुपये हैं। इसके अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल को सीमा चौकियों, निगरानी बुर्ज चौकियों, नावों, इत्यादि तथा डी० आई० जी० मुख्यालय, आई. जी. मुख्यालय तथा बल के मुख्यालय जैसे अन्य पर्यवेक्षी इकाईयों पर भी व्यय करना पड़ता है। सीमा सुरक्षा बल की संख्या की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। अतः उनके द्वारा घुसपैठ, तस्करी इत्यादि गतिविधियों को रोकने पर किसी विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष हुए व्यय का पता लगाना संभव नहीं है।

High Price of Cotton Yarn for Handloom Weavers in Tamil Nadu

313. SHRI M. VINCENT : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) the extent to which the price of cotton yarn was brought down by the various efforts of the Central Government for the handloom weavers;

(b) whether the measures have been implemented throughout the country;

(c) what reasons are being attributed for the high price of cotton yarn for the handloom weavers of Tamil Nadu; and

(d) whether Government will take necessary steps to distribute cotton yarn in hanks to Tamil Nadu handloom weavers at a reasonable rate?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (KUMARI SAROJ KHAPARDE) : (a) to (d) Government has been taking various measures to ensure regular supply of hank yarn at reasonable prices to handloom weavers all over the country. Further in order to safeguard the interests of the handloom sector in the wake of increase in yarn prices Government has been following a cautious policy in permitting exports of cotton and cotton yarn taking into account the requirements of the handloom sector and the domestic price situation. Prices of cotton yarn depend upon the price of cotton on the one hand and speculative factors in the yarn market on the other, as production and trade in the cotton yarn are mainly in private hands. Consequently, prices of yarn have been ruling high till recently. However, prices of hank yarn have stabilised during the past month and have also started showing a declining trend. The extent of fall in prices on account of measures taken by the Government cannot however be quantified.

The reason for the increases in yarn prices in Tamil Nadu besides the ones stated above, is also due to powercuts in the State.

The Government of Tamil Nadu have a system of Yarn Price Fixation Committee under which prices of hank yarn produced by the State/ Cooperative sector spinning mills of Tamil Nadu and supplies to their handloom agencies are fixed, which are usually less than the ruling market price. Existing infrasturcture for supply of hank yarn to the handloom weavers of Tamil Nadu has stood the test of time. By and large complaints received by the Central Government refer to the high prices of hank yarn but do not question the availability and adequacy of yarn. Additionally, Central Government have proposed to set up yarn depots in different parts of the country through the National Development Corporation for supply of han kyarn to